गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम

लेखक-पुलाप्री बालकृष्णन (प्रोफेसर, अशोका यूनिव. सिटी, सोनीपत और सीनियर फेलो, IIM कोझीकोड)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) एवं III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है

द हिन्दू

15 अप्रैल, 2019

"स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान आय समर्थन योजनाओं से अधिक मायने रखता है।"

इस बात को लगभग 50 साल बीत गये हैं जब इंदिरा गाँधी ने भारत में चुनावी क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन का विचार लाया था। उन्होंने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। इंदिरा गाँधी ने वास्तव में अपने शब्दों पर कायम रहकर देश को एक बेहतर दिशा में ले जाने में कुछ हद तक सफलता पायी थी। हालाँकि, यह समस्या उनके समय में मिट नहीं सकी, लेकिन उनके नेतृत्व में अर्थात् 1960 के दशक के उत्तरार्ध में गरीबी में कमी की शुरुआत हो गयी थी।

इसके अलावा, उनके ही नेतृत्व में 1980 के दशक में गरीबी की कटौती में फिर से तेजी आई थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थीं और उन्हें भारतीय होने पर गर्व था। जहाँ एक तरफ भारतीय होने पर गर्व होने के कारण वे लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित थीं, तो वहाँ व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण वे गरीबी उन्मूलन में आय सृजन की केंद्रीयता के बारे में भी जागरूक थीं।

भारत में गरीबी को कम करने में वास्तव में आय सृजन ने जो भूमिका निभाई थी, उसे इन तथ्यों से समझा जा सकता है कि इसके कारण 1980 के दशक में आर्थिक विकास में तेजी आई और 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति के आते ही कृषि उत्पादन तेज हो गया था।

शब्द मायने रखते हैं:-

इसलिए, अब सवाल उठता है कि अगर 50 साल पहले भी गरीबी पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो हमने इसे अब तक समाप्त क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्या के लिए सार्वजनिक नीति का दृष्टिकोण उन योजनाओं को आरंभ करना है जो एक उपशामक अर्थात् पीड़ा हरने वाली योजना से अधिक नहीं हो सकती हैं,जैसा कि इस समय के भाषण में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गरीबी उन्मूलन शब्द से पता चलता है। ये योजनाएं गरीबी की जड़ तक जाने में विफल रहती हैं और इनकी क्षमता में भी कमी होती है जो अंत में किसी व्यक्ति को काम या उद्यमिता के माध्यम से पर्याप्त आय अर्जित करने में असमर्थ बनाते हुए छोड़ देती हैं। आय निर्धनता अभाव का प्रकटीकरण है और विशेष रूप से आय की कमी पर ध्यान केंद्रित करना केवल लक्षण को संबोधित करने के बराबर है।

पार्टियाँ और योजनाएं:-

वर्तमान में चुनावों के लिए, बजटीय हस्तांतरण के माध्यम से गरीबों को आय की गारंटी देने वाली योजनाओं की घोषणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ने की है। जहाँ, बीजेपी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, जो 2 हेक्टेयर तक भूमि की छोटी जोत वाले किसानों को सालाना 6000 रुपए देगी, पहले से ही मौजूद है। जनसंख्या के किसी एक वर्ग के लिए एक आय-सहायता योजना अत्यंत असमान है। हम खेतिहर मजदूरों और शहरी फुटपाथ वासियों के बारे में भी सोच सकते हैं, जो गरीब किसानों के समर्थन के बराबर हैं। वर्तमान में कृषि सब्सिडी अकेले किसानों के पास जाती है, यह उत्पादन सब्सिडी के रूप में हैं और इसलिए सभी को खाद्य उत्पादन की महत्ता के कारण इसे प्रसारित किया जाता है।

दूसरी ओर, एक कल्याण कार्यक्रम समान रूप से शामिल किये गये लोगों को बाहर नहीं कर सकती है। बीजेपी द्वारा जल्दबाजी में पेश की गयी योजना राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ा देती है, जिससे यह समझ में आता है कि उपभोग करने के लिए उधार

लेना होगा, जो वित्तीय रूप से अनुचित अभ्यास है। हालाँकि, पीएम-किसान को कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (NYAY) के वादे ने छोटा बना दिया है, जिसमें सबसे गरीब 20% घरों में 12 गुना अधिक वार्षिक परिकल्पना की गई है। हालांकि, यह योजना भेदभ. ावपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तविक समय में लाभार्थी की पहचान के मुद्दे से इसे काफी चुनौती मिलने वाली है।

दोनों योजनाएं सामने आ गयी हैं, लेकिन विशेष रूप से NYAY की आलोचना अधिक हो रही है, क्योंकि इसमें राजकोषीय स्थान की अनुपस्थिति है।

आईए NYAY योजना को समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा समय में इसमें आने वाली लागत 3.6 लाख करोड़ रूपए प्रतिवर्ष है। यह 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट परिव्यय का लगभग 13% है। यह व्यय राजकोषीय घाटे के लिए किसी भी परिणाम के बिना किया जा सकता है। अगर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को हटा दिया जाये और सब्सिडी में थोडी-सी कमी कर दी जाए।

लेकिन असल मुद्दा यह है कि 13% परिव्यय में, NYAY स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का दोगुना और एक ही बजट में पूंजीगत व्यय से अधिक होगा और ये सार्वजनिक व्यय का ऐसा विषय हैं, जो गरीबी को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, देश में सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की भी भारी कमी मौजूद है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे व्यक्तियों की क्षमताओं के लिए केंद्रीय हैं और एक समाज में उनकी उपस्थिति की सीमा यह निर्धारित करती है कि क्या गरीब, गरीब ही रहेगा या गरीबी से स्थायी रूप से बाहर निकल जाएगा।

आवश्यकता क्या है?

सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) योजना के भारत में कार्यान्वयन के लिए बनाए गए एक ब्लू प्रिंट के प्रकाश में, हम कह सकते हैं कि गरीबी को खत्म करने के परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक स्रोतों से सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं (यूबीएस) की आवश्यकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि वह बजट के माध्यम से वित्तपोषित हो। हमें यूबीआई यूरोपीय अर्थशास्त्रियों से प्राप्त हुआ था। यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है।

यूरोप शायद सार्वजनिक रूप से प्रदान किए गए यूबीएस से संतृप्त है। इसके अलावा इसके कुछ देशों में राज्य काफी समृद्ध है। इसलिए यदि सार्वजनिक आय के एक हिस्से को मूल आय के रूप में भुगतान किया जाता है, तो वहाँ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की परियोजना प्रभावित नहीं होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, जहाँ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक माध्यम के निर्माण का काम गंभीरता से अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

इस बात के अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं की तुलना में गरीबी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान अधिक मायने रखता है। भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर और गरीबी अलग-अलग है। एक विश्वसनीय पैटर्न यह है कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तरी, मध्य और पूर्वी लोगों की तुलना में कम गरीबी है, जो संभवत: पूर्व में उच्च मानव विकास प्राप्ति से संबंधित है।

यह सूचक प्रति व्यक्ति आय के अलावा एक जनसंख्या के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर आधारित है, जो हमें आय सृजन की प्रासंगिकता को गरीबी में वापस लाता है। अब इससे यह सिद्ध होता है कि जब केंद्र सरकार पूरे राज्यों के लिए एक समान है, तो मानव विकास सूचकांक में अंतर राज्य स्तर पर लागू नीतियों के कारण है।

गरीबी दूर करने की क्षमता को बढ़ाने में उत्पादक और उपभोक्ता विविधता दोनों सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि इन सेवाओं को हमेशा बाजार में नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए गरीबी को खत्म करने के लिए अकेले आय समर्थन पर्याप्त नहीं हो सकता है। कम से कम इन सेवाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा पानी, स्वच्छता और आवास की आपूर्ति शामिल होगी।

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि ऐसी सेवाओं की अनुपस्थिति होती है तो भारत में गरीबी वर्तमान में दर्ज की गई तुलना में कहीं अधिक होगी। यह हमें प्रभावी गरीबी को समाप्त करने की चुनौती से निपटने और मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तावित आय-समर्थन योजनाओं की क्षमता का आंकलन करने की अनुमति देता है। गरीबी को समाप्त करने का कोई शॉर्टकट तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन इसे जल्द समाप्त करना भी असंभव नहीं है।

न्यूनतम आय योजना (न्याय, NYAY)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कांग्रेस ने देश की 20 फीसदी सबसे गरीब आबादी को सालाना 72,000 रुपये की मदद देने का वादा किया है और इसे 'न्यूनतम आय योजना' का नाम दिया गया है।
- कांग्रेस की गणना के मुताबिक, देश में 12000 से कम कमाने वाले करीब पाँच करोड़ परिवार हैं।
- प्रति परिवार पाँच आदमियों के औसत से इसके लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ बताई गई है, जो देश की जनसंख्या का करीब 20 फीसदी होती है।

मुख्य बिंदु

- कांग्रेस के आंकड़ों को ही आधार मान लें, तो साल में 72000 रुपये पाँच करोड़ परिवारों को देने में 3.6 लाख करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा।
- मोटे अनुमान के मुताबिक, यह देश की कुल जीडीपी का 1.3 प्रतिशत और मौजूदा वार्षिक बजट का 13 फीसदी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।
- लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 में की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक की तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्रशासित प्रदेशों) में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी, 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ लेने का पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाएगी तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित करेगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद् के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. इसमें लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है, को 6000 रूपये प्रत्येक माह देने का प्रावधान है।
   2. इसकी शुरूआत फरवरी, 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गयी है।
   3. यह पूर्णत: केन्द्र प्रायोजित योजना है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी

1. **Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana.**

   1. There is a provision of providing Rs. 6000 Per month to small and marginal farmers having arable land of 2 hectare.
   2. It has been started from february, 2019 in Gorakhpur.
   3. It is fully centrally sponsored scheme.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3
   (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- भारत में आय समर्थन योजनाओं की अपेक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचों पर अधिक बल देना 'गरीबी उन्मूलन' के लिए कहाँ तक सफल साबित होगा? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. To what extent will emphasising health, education and physical infrastructure instead of income support schemes in India be successful in poverty eradication? Discuss.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट : 13 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।